नं. जेड-14014/1/2021-जीसी एण्ड पार्लि. (ई-3010921)

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,

नई दिल्ली-110011

दिनांक: 15.09.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अगस्त, 2023 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार - के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को अगस्त, 2023 माह के लिए भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

संलग्नकः यथोक्त।

अर्जुन राम

(अर्जुन राणा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23044653

सेवा में,

मंत्री परिषद के सभी माननीय सदस्य

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. भारत के माननीय राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
2. भारत के माननीय उप-राष्ट्रपति के सचिव, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110011
3. भारत के माननीय प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
6. सचिव, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
7. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।

9. सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. सचिव, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली।
12. सचिव, खान मंत्रालय, नई दिल्ली।
13. सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।
14. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
15. सचिव, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
16. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली।
17. सचिव, व्यय विभाग, नई दिल्ली।
18. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।
19. सचिव, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
20. सचिव, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली।
21. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
22. तकनीकी निदेशक, (एनआईसी), भूमि संसाधन विभाग, को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. माननीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री के निजी सचिव।
2. माननीया राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण) के निजी सचिव।
3. माननीय राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास तथा इस्पात) के निजी सचिव।

अगस्त, 2023 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार - के संबंध में।

1. माननीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2023 को कृषि भवन, नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग के **'राष्ट्रीय मीडिया अभियान'** का शुभारंभ किया गया। यह विभाग डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0) नामक योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अखिल भारतीय अभियान चला रहा है। इसका उद्देश्य अपने कार्यक्रमों/योजनाओं, नई पहलों और उपलब्धियों के बारे में आम जनता को जागरूक करना तथा इसके कार्यकलापों में जनता की भागीदारी को बढ़ाना भी है। इस अभियान के पहले चरण में आउटडोर मीडिया, सोशल मीडिया, बल्क एसएमएस और रेडियो जिंगल घटक शामिल हैं। राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज़ रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस), डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई तथा कैक्टस पौधरोपण के बारे में जागरूकता पैदा करने और व्यापक प्रचार करने के लिए दिनांक 11 अगस्त, 2023 को नागरिकों को एक करोड़ एसएमएस भेजे गए तथा पूरे देश में विभिन्न स्थानों जैसे रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डों तथा अन्य प्रमुख स्थानों पर योजनाओं के बारे में होर्डिंग्स/बैनर्स प्रदर्शित किए जा रहे हैं।

2. **पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति (एनएमसी) की 10 वीं बैठक** दिनांक 10 अगस्त, 2023 को सचिव (एलआर) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र से सदस्यों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय निगरानी समिति (एनएमसी) द्वारा पोलावरम सिंचाई परियोजना, केन-बेतवा लिंक परियोजना तथा जेयूएच परियोजना के कारण विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया तथा संबंधित प्राधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई करने के लिए निदेश जारी किए। प्रभावित परिवारों की ओर से डा. पी. पुल्लाराव द्वारा दिए गए अभ्यावेदन में समाविष्ट मुद्दों का सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान किया गया। राष्ट्रीय निगरानी समिति ने आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार समिति को परामर्श देने के लिए दो एक्सपर्ट एसोसिएट की नियुक्ति करने का अनुमोदन दिया।

3. **राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस)** अथवा **ई-रजिस्ट्रीकरण** का अगस्त, 2023 माह में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में शुभारंभ किया गया है। इस प्रकार, एनजीडीआरएस को अब तक 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाया तथा आरम्भ/कार्यान्वित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 12 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एपीआई/यूआई के माध्यम से डेटा को साझा कर रहे हैं।

4. **विश्व बैंक सहायता प्राप्त रिवार्ड (आरईडब्ल्यूएआरडी) कार्यक्रम की दूसरी राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी समिति (एनएलटीसी)** की बैठक पूसा (पीयूएसए), नई दिल्ली में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), एनआरएए की अध्यक्षता में दिनांक 10.08.2023 को आयोजित की गई। इस बैठक में संयुक्त सचिव (डब्ल्यूएम), वरिष्ठ अपर आयुक्त (डब्ल्यूडी) तथा एनपीएमयू विशेषज्ञों ने भाग लिया।

5. सचिव, भूमि संसाधन विभाग की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में **डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई** की प्रगति पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। विभाग द्वारा डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ व्यय, एमआईएस, अमृत सरोवर तथा डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई पर अन्य मुद्दों पर दो समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।

6. विभाग द्वारा खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद में डीआईएलआरएमपी के कार्यान्वयन तथा अन्य मुद्दों के बारे में खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (केएचएडीसी), मेघालय के कार्यकारी सदस्य के साथ बैठक आयोजित की गई।

7. लोक शिकायतों के निपटान के संबंध में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआर एंड पीजी) द्वारा जुलाई, 2023 माह के लिए भूमि संसाधन विभाग को शीर्ष पांच विभागों में स्थान दिया गया।

8. विभाग ने संस्कृति मंत्रालय से प्राप्त निदेशों के अनुसार दिनांक 15 अगस्त, 2023 को 'स्वतंत्रता दिवस' के उपलक्ष्य में सभी कार्मिकों को अपने निवास पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण के लिए अनुदेश जारी किए। इसके अतिरिक्त दिनांक 14 अगस्त, 2023 को राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेल्फी लेने के लिए "एनबीओ बिल्डिंग" में एक "सेल्फी पॉइंट" बनाया गया। अधिकारियों/कर्मचारियों के फोटोग्राफ /सेल्फी को "हर घर तिरंगा" पोर्टल पर अपलोड किया गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर व्यापक रूप से परिचालित किया गया।

9. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के वॉटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के तहत, कुल 6382 {8214 (स्वीकृत) - 1832 (राज्यों को अंतरित)} परियोजनाओं में से अब तक 6376 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अभी तक 6061 परियोजनाओं की एंड लाइन मूल्यांकन रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं।

10. डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के विभिन्न घटकों की प्रगति (संचयी) की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

(i) 6,22,773 गांवों के भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण पूरा किया गया।

(ii) 4,968 उप रजिस्ट्रार कार्यालयों में रजिस्ट्रीकरण का कंप्यूटरीकरण पूरा किया गया।

(iii) 1,30,72,020 भूकर मानचित्रों/एफएमबी/टिप्पनों का डिजिटलीकरण पूरा किया गया।

(iv) 4,360 उप रजिस्ट्रार कार्यालयों का भूमि अभिलेखों के साथ एकीकरण पूरा किया गया।

(v) 3,327 तहसीलों में आधुनिक अभिलेख कक्षों की स्थापना पूरी की गई।

*****